

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 17 नवम्बर, 2008 / 26 कार्तिक, 1930

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अधिसूचिनाएं

शिमला-2, 4 मार्च 2008

संख्या कल्याण-ए(4) 3/95—I.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्तक शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयाग के परामर्श से हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, में लिपिक, वर्ग—III (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध —'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का सक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, लिपिक, वर्ग—III, (अराजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नित नियम, 2007 हैं।
 - (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

- 2. निरसन और व्यावृत्तियां.—(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या कल्याण—ए (4)—3 / 95, तारीख 31—3—1997 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश समाज एवं महिला कल्याण विभाग, लिपिक (वर्ग—III, अराजपित्रत) लिपिक वर्गीय सेवाएं भर्ती एवं प्रोन्नित नियम, 1997 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप—नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित / — प्रधान सचिव ।

उपाबन्ध-क

हिमाचल प्रदेश, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में लिपिक, वर्ग—III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नित नियम।

- **1. पद का नाम**—लिपिक :
- **2. पदों की संख्या**—249 (दो सौ उनचास)
- 3. वर्गीकरण-वर्ग-III (अराजपत्रित) (लिपिक वर्गीय सेवाएं)
- **4. वेतनमान** (विस्तृत रूप में दिया जाए)—3,120—100—3,220—110—3,660—120—4,260—140—4,400—150—5,000—160—5,160 रूपए। प्रारम्भिक आरम्भ 3220 / के साथ ।
- **5. चयन पद अथवा अचयन पद**—अचयन पद ।
- **6.** सीधी भर्ती के लिए आयु—18 से 45 वर्ष ।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है:

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/ किए गए थे।

(i) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसके पद (पदों) को आवेदन आमत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

- (ii) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।
- 7. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.—(क) अनिवार्य अर्हता : किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड / विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में दसवीं पास या 10+2 की परीक्षा पास की हो या इसके समकक्ष ।

अंग्रेजी टंकण में कम से कम तीस शब्द प्रति मिनट और हिन्दी टंकण में पच्चीस शब्द प्रति मिनट की गति रखता हो।

- (ख) वांछनीय अर्हता(एं)—हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
- 8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शाँक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगीं या नहीं.— आयु: लागू नहीं । शैक्षणिक अर्हता: जैसी की स्तम्भ न. 11 में प्रावधित है।
- 9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.— दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।
- 10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नित, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.—(1) 90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर ।
 - (2) 10 प्रतिशत प्रोनन्ति द्वारा ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा या संविदा आधार पर ।
- 11. प्रोन्नित, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नित, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.—वर्ग—IV कर्मचारियों में से प्रोन्नित द्वारा, जो दसवीं पास हो या जिन्होंने मैट्रिक के अंग्रेजी विषय सिहत हिन्दी (रत्न) पास किया हो और जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।

परन्तु करूणामूलक आधार पर इस प्रकार प्रोन्नित या नियुक्त वर्ग—IV पदधारियों को, जो ऐसी नियुक्ति के समय मैट्रिक पास (तृतीय श्रेणी) या मैट्रिक के अंग्रेजी विषय सिहत हिन्दी रत्न पास की शैक्षिक अर्हताएं रखते हो को तब तक वरिष्ठ सहायक के पद पर उनकी आगामी प्रोन्नित के लिए विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे स्तम्भ संख्या 7 में सीधी भर्ती के लिए यथा विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं प्राप्त नहीं कर लेते ।

परन्तु पात्र वर्ग—IV कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान के माध्यम से कार्यालय प्रिकया, टंकण और शब्द प्रसंस्करण में दो मास का प्रशिक्षण या तो संस्थान में या उनके अपने—अपने जिला प्रशिक्षण केन्द्रों में दिया जाएगा । प्रशिक्षित अभ्यर्थी प्रोन्नित के लिए पात्र होंगे । प्रशिक्षण केवल एक बार ही दिया जाएगा, परन्तु जो पहली बार परीक्षा पास करने में असमर्थ रहते हैं, उनको समय समय पर परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाएगा।

प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए वर्ग—IV कर्मचारियों की, उनके सेवाकाल के आधार पर उनकी संवर्गवार पारस्परिक वरिष्ठता को छेड़े बिना एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी ।

(1) प्रोनिन्त के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरण पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो प्रोन्नित के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरण प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नित भर्ती एवं प्रोन्नित नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात की गई थी:

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई किनष्ठ व्यक्ति सम्भरण पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सिहत, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हा) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने—अपने प्रवर्ग/पद/कांडर में उससे विष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय किनष्ठ व्यक्ति से उपर रखे जाएंगे:

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नित के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नित नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नित किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे किनष्ट व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नित के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा / समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण.—अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत किनष्ठ पदधारी प्रोन्नित के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि विरष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम—3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम—3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हो ।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति / प्रोन्नित से पूर्व सम्भरण पर पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नित उचित चयन के पश्चात् और भर्ती एवं प्रोन्नित नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

- **12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.**—जैसी सरकार द्वारा समय—समय पर गठित की जाए ।
 - 13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
- 14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।
- 15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा । यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।
- 15. (क) संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—(i) संकल्पना.—(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, में लिपिक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर दो और वर्षों के लिए बढाया जा सकेगा।
- (ख) निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के समक्ष रखेगा ।

- (ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।
- (घ) इन नियमों के अधीन इस प्रकार चयनित संविदा पर नियुक्त लिपिक को सरकारी सेवा(जॉब) में नियमितिकरण या स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा ।
- (II) संविदात्मक उपलिख्यां.—संविदा के आधार पर नियुक्त लिपिक को 4,830 / रूपए की दर से संविदात्मक रकम (जो प्रारम्भिक वेतनमान जमा महंगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जायेगी। अनुपस्थिति की अविध के लिए कोई रकम संदत्त नहीं की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढौतरी की जाती है तो क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक उपलिब्धयों में 100 / रूपए वाषिर्क वृद्धि के रूप में अनुज्ञात किए जाएंगे।
- (iii) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.— निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।
- (iv) चयन प्रक्रिया.— संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यकम सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाएगा
- (v) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन सिमिति.—जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा गठित की जाए ।
- (vi) करार.— अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध—ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।
- (vii) निबन्धन एवं शर्ते.— (क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 4,830 /— रूपए की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो प्रारम्भिक वेतनमान जमा महंगाई वेतन के बराबर होगी प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक रकम में 100 /— रूपए की दर से वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाओं, जैसे वरिष्ठ / चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।
- (ख) संविदा पर नियुक्त लिपिक की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है ।
- (ग) संविदात्मक नियुक्ति, पदधारी को किसी भी दशा में सेवा में नियमितिकरण का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।
- (घ) संविदा पर नियुक्त लिपिक, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकिस्मक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त लिपिक को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी । केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा ।
- (ड) कार्यालय अध्यक्ष के अनुमोदन के बिना सेवा से अनिधकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की समाप्ति (पर्यावसान) हो जाएगी । संविदा पर नियुक्त लिपिक कर्तव्य (ड्यट्री) से अनुपस्थिति की अविध के लिए किसी संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।
- (च) संविदा पर नियुक्त लिपिक का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

- (छ) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना अरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।
- (ज) संविदा पर नियुक्त लिपिक का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।
- (VIII) नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकार इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए अभ्यर्थी को, किसी भी दशा में विभाग में लिपिक के रूप में नियमितिकरण / स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा ।
- 16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय—समय पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदशों के अधीन होगी ।
 - 17. विभागीय परीक्षा.— लागू नहीं ।
 - 18. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

उपाबन्ध-ख

लिपिक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से निष्पादित की जाने वाले संविदा / करार का प्ररूप।

यह करार श्री / श्रीमति	पत्र / पत्री श्रीपत्र /	निवासी
संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इस		
के राज्यपाल के मध्य, निदेशक सामाजिक		
'द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम रं	ने आज तारीख व	को किया गया ।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने लिपिक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तो पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:—

- 1. यह कि प्रथम पक्षकार लिपिक के रूप मेंसे प्रारम्भ होने और......को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अविध के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात......दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।
- 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 4830 / रूपए प्रतिमास होगी ।
- 3 प्रथम पक्षकार की सेवा बिल्कुल अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध

नियुक्त / तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए दायी होगी ।

- 4 संविदात्मक नियुक्ति, किसी भी दशा में नियमित सेवा के लिए पदधारी को कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।
- 5. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकिस्मक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिक्तिसा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी । केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा ।
- 6 नियंत्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य(कार्य) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।
- 7. संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा ।
- 8. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए ।
- 9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति को यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी ।
- 10. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ—साथ इ.पी.एफ./ जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा। इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थित में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने—अपने हस्ताक्षर कर दिए है।

साक्षी की उपस्थिति में	
1	
(नाम व पूरा पता) 2	
	प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर
1	
(नाम व पूरा पता)	
2	
(नाम व पुरा पता)	द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर

[Authoritative English Text of this department notification No Kalyan-A(4)3/95-I, dated -----as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India.]

DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4 March, 2008

- **No. No Kalyan-A** (4)3/95-I.— In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh,in consultation with the H.P Public service commission is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Clerk Classs-III(Non-Gazetted) Ministerial Service in the Department of Social Justice and Empowerment, Himachal Pradesh as per Annexure-A attached to this notification, namely:—
- **1.** Short title and Commencement.—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh, Social Justice & Empowerment Department, Clerk ,Class-III-(Non- Gazetted), Ministerial Service Recruitment and Promotion, rules, 2007.
- (2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
- **2.** Repeal & Savings.— (1) The Himachal Pradesh Social Justice & Women's Welfare Department, Clerk, (Class-III Non Gazetted) Ministerial Service Recruitment and Promotion rules, 1997 notified vide this Department notification No. WLF-A (4)- 3/95 dated 31.3.1997 are hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal any appointment made or any thing done or any action taken under the rules, so repealed under sub-rule (1) supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order, Sd/-Pr. Secretary.

Annexure-A

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF CLERK (NON-GAZETTED) CLASS-III IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE & EMPLOYMENT, HIMACHAL PRADESH

1. Name of the Post : Clerk

2. Number of posts: 249 (Two hundred forty nine)

3. Classification : Class-III (NON-GAZETTED) Ministerial Services.

4. Scale of pay (be given in expanded notation): 3120-100-3220-110-3360-120-4260-140-4400-150-5000-160-5160 with an initial start of Rs. 3220/-

- **5. Whether Selection or Non-Selection post :** Non-Selection.
- **6. Age for direct recruitment :** Between 18 and 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including these who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporation and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the public sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporation/Autonomous Bodies after initial constitutions of the Public sector Corporations/Autonomous Bodies.

- (i) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.
- (ii) Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the H.P. Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.
- 7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruits: (a) **ESSENTIAL QUALIFICATION** (i) Should have passed Matriculation examination with second division or 10+2 Examination or its equivalent from a recognised University/ Board.
- (ii) Should possess a minimum speed of 30 words per minute in English typewriting or 25 words per minute in Hindi typewriting.
- **(b) DESIRABLE QUALIFICATIONS**: Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
- 8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotes: Age:-----No. Educational qualification --- As prescribed in Colonum No. 11 below.
- **9. Period of probation, if any.** Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be record in writing.

- 10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post to be filled in by various methods.— 90% by Direct recruitment or on contract basis and 10% by promotion failing which by direct recruitment or on contract basis.
- 11. In case of recruitment by promotions, deputation, transfer grade from which promotion/deputation/ transfer is to be made.—By promotion from amongst the Class- IV officials who have passed Matric or Hindi (Rattan) with Matric (English as one of the subject) and also possess 5 years regular service or regular combined with continuous adhoc service if any, in the grade.

For the purpose of promotion a combined seniority of all eligible class-IV employees on the basis of length of service without disturbing their cadrewise inter-se-seniority shall be prescribed.

Provided that 2 months training to the eligible class-IV employees will be given in office procedure, typewriting and word processing through HIPA either at the Institute or at their respective District Training Centres. Trained candidates will be eligible for promotion. Training will be held only once but opportunity for appearing in the test will be given from time to time to those who are unable to pass the test in one go.

Provided further that those clerks who have been promoted from amongst the Class-IV employees or appointed on compassionate grounds having the educational qualification of Matric 3rd Division or Matric (in English only) and Hindi Rattan pass at the time of such promotion/appointment shall not be considered to eligible for their next promotion for the post of senior Assistant until they possess the minimum education qualification prescribed for direct recruitment in col. No. 7 above.

- (1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of Recruitment and Promotions Rules, provided that:-
- (i) in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service on adhoc basis followed by regular service appointment in the feeder post in view of the provisions referred to above all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotions shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the Post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the recruitments of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non- Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of

seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service. If the adhoc appointment/promotion had been after proper selection and in accordance with the provision of Recruitment and Promotion Rules;

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account adhoc service rendered shall remain unchanged.

- 12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.
- 13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.— As required under the law.
- 14. Essential requirement for direct recruitment.—A candidate for appointment to any service post must be a citizen of India.
- 15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall made on the basis of viva-voce test and if Himachal Pradesh Public Service commission or other recruiting authorities as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard syllabus etc. of which, will be determined by the commission/other recruiting authority as the case may be.

15A. Selection for appointment to the post by contract appointment.—(i) CONCEPT.

- (a) Under this policy, the Clerk in the Department of Social Justice & Empowerment, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable for two more years on year to year basis.
- (b) The Director, Social Justice & Empowerment after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. SSSB.
- (c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions as prescribed in these Rules.
 - (d) Contract appointee so selected under these rules will not have any right to claim for regularization or permanent absorption in the Government Job.
 - (ii) **Contractual Emoluments:** The Clerk on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs 4830/- P.M.(which shall be equal to initial of the pay scale+Dearness pay). An amount of Rs 100/-(equal to annual increase in the pay scale of the post) as per annual increase in contractual emoluments for the second and third years respectively will be allowed if contract is extended beyond one year.
 - (iii) **APPOINTING /DISCIPLINARY AUTHORITY**: Director of Social Justice & Empowerment H.P. will be appointing and disciplinary authority.

- (iv) SELECTION PROCESS: Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency *i.e.* HPSSSB.
 - (V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS: As may be constituted by the concerned recruiting agency *i.e.* the H.P.S.S.S.B. from time to time.
- **(VI) AGREEMENT**: After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.
- **(VII) TERMS AND CONDITIONS:** (a) The contract appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 4830/- per month(which shall be equal to initial of the pay scale + dearness pay). The Contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 100/-(equal to annual increase in the pay scale) per annum for second and their years respectively and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given .
- (b) The service of the Contractual appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
- (c) Contractual appointment shall not confer any right to the incumbent for the regularisation in service at any state.
- (d) Contractual appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No. leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per Rules.
- (e) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
- (f) Transfer of a contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.
- (g) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidates pregnant beyond twelve weeks will stet temporally unfit till the confinement is over. The women candidate will be reexamined for fitness from an authorized Medical officer/Practitioner.
- (h) Contract appointee will be entitled to TA/ DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of the pay scale.
- **(VIII) RIGHT TO CLAIM REGULAR APPOINTMENT:** The candidate engaged on contract basis under these rules shall have no right to claim regularization/ permanent absorption as Clerk in the Department at any stage.

- **16. Reservation.**—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for scheduled castes/Sch. Tribes/other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
- 17. Powers to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.

Annexure-B

Form of contract/agreement to be executed between the Clerk_& the Government of Himachal Pradesh through Director Social Justice & Empowerment Department.

	This	agreement	is	made	on	this	day	of		in	the
year	•••••	Between Sh.	./Smt./	Km		S/o/D/o	Sh	ri	R/o		
				cor	ıtract	appointee(he	ereinafter ca	lled the I	FIRST PAR	ΓΥ), Δ	And
The C	overno	or, Himacha	l Prad	esh th	rough	Director, So	ocial Justice	and Em	powerment	Hima	chal
Prades	sh (here	e-in-after ca	lled th	e SEC	ONI	PARTY) T	he second p	arty has o	engaged the	afore	said
FIRS 7	PAR	ΓY and the	FIRS'	Т РАБ	RTY	has agreed to	o serve as (Clerk on	contract bas	is on	the
follow	ing ter	ms & condit	ions:-	_							

- 2. The contract amount of the FIRST PARTY will be Rs 4830/- Per month.
- 3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
- 4. The contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regularization of service at any stage.
- 5. Contractual appointee will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the Contractual appointee. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
- 6. Un-authorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual appointee will not be entitle for contractual amount for the period of absence from duty.

- 7. Transfer of a official appointed on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.
- 8. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
- 9. Contractual appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counterpart Official at the minimum of the pay scale.
- 10. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

WITNESS THE FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

1	
(Name and Full Address)	
2	(Signature of the First party)
(Name and Full Address)	(Signature of the Second Party)
2	
(Name and Full Address).	
	_

शिमला-2, 17अक्तूबर, 2008

संख्या डब्ल्यू, एल. एफ. — ए(3) 71996. — हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुछेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयागे करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयागे के परामर्श से हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में संगणक, वर्ग—III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध — 'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नित नियम बनाती हैं अर्थात्:—

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, संगणक वर्ग—III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नित नियम, 2008 हैं ।
 - (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित / – प्रधान सचिव।

उपाबन्ध-क

हिमाचल प्रदेश, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में संगणक, वर्ग—III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नित नियम

1. पद का नाम : संगणक

2. पदों की संख्या : 6 (छह)

3. वर्गीकरण : वर्ग-III (अराजपत्रित)

4. वेतनमान : 3120-100-3220-110-3660-120-4260-140-4400-150-5000-160-5160 रू0

5. चयन पद अथवा अचयन पद : अचयन पद

6. सीधी भर्ती के लिए आयु : 18 से 45 वर्ष।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी, इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छटू के लिए पात्र नहीं होगा;

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा में उतनी छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है;

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर, निगमों स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों रवायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर, निगमों स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् निगमों रवायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं /िकए गए थे।

- (1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद / पदों को, आवेदन आमंत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
- (2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।
- 7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.— अनिवार्य अर्हर्तता : (i) मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में 10+2 पास हो या इसके समकक्ष।
 - (ii) मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर डिपलोमा ।

- वांछनीय अर्हर्तताएं : (i) हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में टंकण का ज्ञान और इस क्षेत्र (लाईन) का अनुभव।
- (ii) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान आरै प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
- 8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत किए गए व्यक्तियों की दशा में लागू होगीं.—आयु : लागू नहीं, शैक्षिक अर्हता : लागू नहीं।
- 9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.—दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनिधक ऐसी और अविध के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी, विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।
- 10. भर्ती की पद्वतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नित, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.—शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर ऐसा न होने पर स्थानान्तरण द्वारा ।
- 11. प्रोन्नित, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणिया(ग्रडे), जिनसे प्रोन्नित, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.—स्तम्भ संख्या— ७ के सामने यथाविहित अनिवार्य अर्हता रखने वाले कर्मचारियों तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों में इस ग्रेड के समतुल्य पद धारणा करने वाले कर्मचारियों में से स्थानान्तरण द्वारा।
- **12. यदि विभागीय प्रोन्नित समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.**—जैसी सरकार द्वारा समय—समय पर गठित की जाए।
- 13. किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
- 14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.—किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यार्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।
- 15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.—सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा । यदि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।
- 15—क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन (नया अपबन्ध).—(I) संकल्पनाः (क) इस पालिसी के अधीन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश में संगणक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर दो और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा ।
- (ख) निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के समक्ष रखेगा ।
 - (ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।
- (घ) इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर इस प्रकार चयनित व्यक्ति को सरकारी सेवा (जॉब) में नियमितिकरण या स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

- (II) संविदात्मक उपलिख्यां : संविदा के आधार पर नियुक्त संगणक को 4680 / रूपए की संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक उपलिख्यों में 100 / रू० की वृद्धि अनुज्ञात की जागगी।
- (III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारीः निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।
- (IV) चयन प्रिकेयाः संविदा पर नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्त के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाएगा।
- (V) संविदात्मक नियुक्कितयों के चयन के लिए समितिः जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा समय—समय पर गठित की जाए ।
- (VI) करारः अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमो से संलग्न उपाबन्ध—"ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।
- (VII) निबन्धन एवं शर्तें : (क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 4680 / रू० की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक रकम में 100 / रू० की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे विष्ठ / चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।
- (ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है।
- (ग) संविदात्मक नियुक्ति, पदधारी को किसी भी दशा में, सेवा में नियमितिकरण का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगीं।
- (घ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकिस्मक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक क्लैंडर वर्ष में बारह दिन तक संचित किया जा सकेगा और एक क्लैंडर वर्ष के अन्त में व्यपत्रत हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसर दिया जाएगा।
- (ङ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनिधकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा पर्यवसान (समाप्ति) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, कर्तव्य से अनुपस्थिति की अविध के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।
- (च) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
- (छ) चयनित अभ्यर्थी को, सरकारी / रिजस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। महिला अभ्यर्थी का प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

- (ज) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा।
- (VIII) नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकार : इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर लगाए गए अभ्यर्थी को किसी भी दशा में विभाग में संगणक के रूप में नियमितिकरण / स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- 16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय—समय पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों और प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदशों के अधीन होगी ।
 - **17. विभागीय परीक्षा.**—लागू नहीं ।
- 18. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

"उपाबन्ध-ख"

संगणक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री / श्रीमतिपुत्र / पुत्री श्रीपुत्र निवासीनिवासी
संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रश्थम पक्षकार' कहा गया है), ओर हिमाचल प्रदैश
के राज्यपाल, के मध्य निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात
'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से, आज तारीख को किया गया। द्वितीय पक्षकार ने
उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने संगणक के रूप में संविदा के आधार पर
निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:

- 1. यह कि प्रथम पक्षकार संगणक के रूप मेंसे प्रारम्भ हाने और......को समाप्त हाने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पज्ञकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्......दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।
- 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 4680 / रूपए प्रतिमास होगी । 3 प्रथम पक्षकार की सेवा बिल्कुल अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त / तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) किए जाने के लिए दायी होगी ।
- 3. संविदात्मक नियुक्ति, किसी भी दशा में नियमित सेवा के लिए पदधारी को काई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।
- 4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को, किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा ।

वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी । केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा ।

- 5. नियंत्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनिधकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्यों (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अविध के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।
- 6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए किसी भी दशा में स्थानान्तरण अनुज्ञात नहीं होगा ।
- 7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रिजस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक समय की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए ।
- 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी ।
- 9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(व्यक्तियों) को सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ—साथ इ.पी.एफ. / जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा ।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार साक्ष्यों की उपस्थिति में सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने—अपने हस्ताक्षर कर दिए है ।

साक्षियों की उपस्थिति में	
1	
(नाम व पूरा पता) 2	
(नाम व पूरा पता)	प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर
साक्षियों की उपस्थिति में	
1	
(नाम व पूरा पता)	
2	
(नाम व पूरा पता)	द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर

(Authoritative English Text of this department notification NoWLF-A(3)15/2005, dated ----- as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India.)

DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 17th October, 2008

No. WLF-A(3)15/2005—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Computer, Class-III(Non-Gazetted)in the Department of Social Justice and Empowerment, Himachal Pradesh as per Annexure-A attached to this notification, namely:—

- **1.** *Short title and Commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Social Justice & Empowerment Department, Computer, Class-III-(Non-Gazetted), Recruitment and Promotion, Rules, 2008.
 - (2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order, Sd/-Pr. Secretary.

Annexure-A

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF COMPUTER (NON-GAZETTED) CLASS-III IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE & EMPLOYMENT, HIMACHAL PRADESH

1. Name of the Post: COMPUTER

2. Number of posts: 06 (Six)

3. Classification: Class-III (NON-GAZETTED)

Scale of pay (be given in expanded notation) : 3120-100-3220-110-3660-120-4260-140-4400-150-5000-160-5160.

5. Whether Selection or Non-Selection post: Non Selection

6. Age for direct recruitment: Between 18 and 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including these who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other Backward categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporation and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the public sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporation/Autonomous Bodies after initial constitutions of the Public sector Corporations/Autonomous Bodies.

- (i) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.
- (ii) Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the H.P. Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.
- 7. Minimum Educational qualification and other qualifications required for direct recruits.—a) ESSENTIAL: (i) Should have passed Matriculation with second division or 10+2 Examination or its equivalent from a recognised Board/University.
 - (ii) Computors Diploma from a recognised Institute.
- **(b) DESIRABLE QUALIFICATION :** (i) Knowledge of typewriting both in Hindi and English and experience in the line.
- (ii) Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
- 8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotes.—Age:-----N.A. Educational qualification---N.A.
- **9. Period of probation, if any**.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
- 10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post to be filled in by various methods.—100% By Direct recruitment or on contract basis failing which by transfer.
- 11. In case by recruitment by promotions, deputation, transfer, grade from which promotion/ deputation/transfer is to be made.—By transfer from amongst the officials possessing essential qualification as prescribed against Col.No.07 and holding equivalent post in the grade in other Departments of H.P. Government.
- 12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.

- 13. Circumstances under which the H.P.Public Service Commission to be consulted in making recruitment.—As required under the law.
- **14. Essential requirements for direct recruitment.**—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
- 15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post or in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test, if H. P. Public Service commission or other recruiting authorities as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard syllabus etc. of which, will be determined by the commission/other recruiting authority.
- 15A. Selection for appointment to the post by contract appointment (New Provision).—(i) CONCEPT.
- (a) Under this policy, the Computer in the Department of Social Justice & Empowerment, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable for two more years on year to year basis.

The Director, Social Justice & Empowerment after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

- (c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions as prescribed in these Rules.
- (d) Contract appointee so selected under these rules will not have any right to claim for regularization or permanent absorption in the Government Job.
- (ii) Contractual Emoluments: The Computer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs 4680/- P.M.(which shall be equal to initial of the pay scale+Dearness pay). An amount of Rs 100/- as per annual increase in contractual emoluments for the second and third years respectively will be allowed if contract is extended beyond one year.
- (iii) APPOINTING /DISCIPLINARY AUTHORITY: Director of Social Justice & Empowerment H.P. will be appointing and disciplinary authority.
- (iv) SELECTION PROCESS: Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. HP Subordinate Service Selection Board.
- (v) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS: As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P Subordinate Service Selection Board from time to time.
- (vi) AGREEMENT: After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.
- (vii) TERMS AND CONDITIONS: (a) The contract appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs.4680/- per month(which shall be equal to initial of the pay scale + dearness pay). The Contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs.

100/- per annum for second and third years respectively and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given .

- (b) The service of the Contractual appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
- (c) Contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regularization in service at any stage.
- (d) Contractual appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto twelve days in a calendar year and casual leave not availed in calendar year shall elapse on the close of a calendar year. No. leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per Rules.
- (e) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
- (f) Transfer of a contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.
- (g) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidates pregnant beyond twelve weeks will be temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for fitness from an authorized Medical officer/Practitioner.
- (h) Contract appointee will be entitled to TA/ DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of the pay scale.
- (viii) RIGHT TO CLAIM REGULAR APPOINTMENT: The candidate engaged on contract basis under these rules shall have no right to claim regularization/ permanent absorption as Computer in the Department at any stage.
- **16. Reservation.** The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for scheduled castes/Sch. Tribes/other Backward Classes/ Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
- 17. Powers to Relax.—Where the State Government. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.

Annexure-B

	Form	of	contract/	agreement	to	be	executed	between	the	Compu	iters	Government	of
Himach	nal Pra	desh	through	Dierector	Soc	ial J	ustice & E	mpowern	nent I	Departm	ent T	This agreemen	ıt is
made	on	th	is	d	ay	of		i	n	the y	ear	Betwo	een
Sh/Smt	/Km			S/O/D/O			Shri		R/c)			

- 2. The Consolidated contractual amount of the FIRST PARTY will be 4680/- Per month.
- 3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
- 4. The contractual appointment shall not confer any right to incumbent for the regularization of service at any stage.
- 5. Contractual......(Name of the post) will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the Contractual......(Name of the post). He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
- 6. Un-authorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual(Name of the post)will not be entitle for contractual amount for the period of absence from duty.
- 7. Transfer of a official appointed on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.
- 8. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
- 9. Contractual appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counterpart Official.
- 10. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS THE FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

1	
(Name and Full Address)	(Cinnature of the First marter)
2	(Signature of the First party)
(Name and Full Address)	(Signature of the Second Party)
2	(2-8
(Name and Full Address)	

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2. 15 नवम्बर. 2008

संख्या ई०एक्स०एन—एफ(1)—2/99—पार्ट—I.——हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973(1973 का अधिनियम संख्यांक 2) की धारा 293 के संदर्भ में, भारत के संविधान के अनुच्छदे 162 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, श्री चमन लाल वैज्ञानिक अधिकारी(रसायन विज्ञान एवं विष विज्ञान) को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 293 के प्रयोजन के लिए, स्वापक औषिधयों और मनः प्रभावी पदार्थों के नमूनों का रासायनिक परीक्षण करने हेतु जनहित में सहायक रसायन परीक्षक घोषित करती है ।

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल यह भी निर्देश देती हैं कि रसायन परीक्षक और सहायक रसायन परीक्षक, कम्पोजिट टेस्टिंग लेवोरेटरी, कण्डाघाट जिला सोलन, भी हिमाचल प्रदेश राज्य में यथा लागू स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985(1985 का 61) और पंजाब एक्साईज ऐक्ट, 1914(1914 का 1) के अधीन स्वापक औषधियों और मनः प्रभावी पदार्थों तथा मादक द्रव्यों के नमूनो का विश्लेषण और परीक्षण यथावत करते रहेंगे तथा इस बावत रिर्पोटें प्रस्तुत करते रहेंगे ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित / — प्रधान सचिव।

[Authoritative English text of this department notification No.EXN-F(1)-2/99-Pt-I dated 15-11-2008 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.]

EXCISE & TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 15th November, 2008

No. EXN-F(1)-2/99-Pt-I.—With reference to section 293 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No 2 of 1973), the Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by Article 162 of the Constitution of India, is pleased to declare Shri Chaman Lal,

Scientific Officer (Chemistry & Toxicology) as Asstt. Chemical Examiner for the chemical examination of samples of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances in the public interest for the purpose of section 293 of the Criminal Procedure Code, 1973.

The Governor of Himachal Pradesh is further pleased to direct that the Chemical Examiner and Asstt. Chemical Examiner, Composite Testing Laboratory, Kandaghat, District Solan shall also continue to analyze/test the samples of Narcotics Drugs and Psychotropic Substances and Intoxicants under the Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985) and the Punjab Excise Act, 1914(1 of 1914) as applicable to Himachal Pradesh and to furnish reports in regard thereto.

By order, Sd/-Principal Secretary.

ब अदालत श्री जे0 आर0 भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सिहुन्ता, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

केस नम्बर 22—3—XIII-B/08. तारीख पेशी 5—12—2008.

श्री गगन सिंह उर्फ गगन चन्द पुत्र श्री नन्दू राम, निवासी लोधरगढ़, पंचायत धुलारा, उप–तहसील सिहुन्ता, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

सर्व साधारण जनता को सूचित किया जाता है कि श्री गगन सिंह उर्फ गगन चन्द पुत्र श्री नन्दू राम, निवासी लोधरगढ़, पंचायत धुलारा, उप–तहसील सिहुन्ता, जिला चम्बा ने इस अदालत में आवेदन–पत्र दिया है कि उसका नाम गगन चन्द दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग में गगन सिंह दर्ज है प्रार्थी अपने नाम की दरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः अग्रिम कार्यवाही से पहले सर्व साधारण जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस नाम गगन सिंह उर्फ गगन चन्द पुत्र श्री नन्दू राम, निवासी लोधरगढ़, पंचायत धुलारा को राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई आपित हो तो वह दिनांक 5—12—2008 को सुबह 10.00 बजे मौखिक या लिखित रूप में असालतन या वकालतन एतराज पेश कर सकते हैं। यदि उपरोक्त दिनांक को कोई उजर/एतराज पेश न हुआ तो यह समझा जायेगा कि उक्त नाम को राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज न है और नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 1-11-2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

जे0 आर0 भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सिहन्ता, जिला चम्बा (हि0 प्र0)। ब अदालत श्री जे0 आर0 भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सिह्न्ता, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

केस नम्बर 23—3—XIII-B/08. तारीख पेशी 10—12—2008.

श्री प्रेम चन्द उर्फ प्रेम सिंह पुत्र भगत राम, निवासी डोरडा डा० गरनोटा, पंचायत कामला, उप—तहसील सिहुन्ता, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि श्री प्रेम चन्द उर्फ प्रेम सिंह पुत्र श्री भगत राम, निवासी डोरडा, पंचायत कामला, उप—तहसील सिहुन्ता, जिला चम्बा ने इस अदालत में आवेदन—पत्र दिया है कि उसका नाम प्रेम सिंह दर्ज है लेकिन राजस्व रिकार्ड में प्रेम चन्द दर्ज है प्रार्थी अपने नाम की दरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः अग्रिम कार्यवाही से पहले सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस नाम प्रेम चन्द उर्फ प्रेम सिंह पुत्र श्री भगत राम, निवासी डोरडा, पंचायत कामला को राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई आपित हो तो वह दिनांक 10—12—2008 को सुबह 10.00 बजे मौखिक या लिखित रूप में असालतन या वकालतन एतराज पेश कर सकते हैं। यदि उपरोक्त दिनांक को कोई उजर / एतराज पेश न हुआ तो यह समझा जायेगा कि उक्त नाम को राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज न है और नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 1–11–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

जे0 आर0 भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सिहुन्ता, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री प्रताप सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार भटियात, चुवाड़ी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री पूर्ण बहादुर पुत्र श्री राम प्रसाद, निवासी ककीरा, तहसील भटियात, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी।

विषय.——प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत ककीरा कस्वा, तहसील भटियात, जिला चम्बा (हि0 प्र0) में अपनी दादी श्रीमती देवी माया विधवा श्री करण बहादुर की मृत्यु दर्ज करवाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र व ब्यान हल्फी इस आश्य से गुजारा है कि प्रार्थी की दादी श्रीमती देवी माया जिसकी मृत्यु दिनांक 15—2—1964 को हुई है जो ग्राम पंचायत ककीरा कस्वा के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को बजरिया सूचित किया जाता है कि श्रीमती देवी माया की मृत्यु ग्राम पंचायत ककीरा कस्वा में यदि दर्ज करने पर किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 1—12—2008 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत में होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न होने की सूरत में उपरोक्त मृत्यु तिथि पंजीकरण के आदेश दे दिए जायेंगे।

आज दिनांक 1-11-2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

प्रताप सिंह ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भटियात, चुवाड़ी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री इन्द्र सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री राज कुमार सुपुत्र श्री देस राज, निवासी बस स्ट्रै डलहौजी, डाकघर डलहौजी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र मय ब्यानहल्फी इस आश्य से गुजारा है कि उसकी पुत्रियां Diksha, Khushbu, Nandani की जन्म तिथियां क्रमशः 3–5–1999, 14–12–2001, 10–7–2004 है, जोकि नगर परिषद् डलहौजी के रिकार्ड में दर्ज न है, जिन्हें दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित पुत्रियों की जन्म तिथियां नगर परिषद् के रिकार्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 8—12—2008 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 27-10-2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

इन्द्र सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

केस० नं० : त० सां० (रीडर) :---

तारीख फैसला 4-11-2008.

श्री सरजन सिंह पुत्र श्री पदम सैन, गांव कामरु, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

श्री राम पाल पुत्र श्री पदम सैन, गांव कामरु, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

. . प्रत्यार्थीगण।

आम जनता, उप–महाल कामरु, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

दरख्वास्त बावत मकफूल उल खबरी राम पाल, ग्राम कामरु।

आदेश

प्रार्थी श्री सरजन सिंह पुत्र श्री पदम सैन, गांव कामरु, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि मकफूद उल खबरी की श्री राम पाल, निवासी कामरु, तहसील सांगला जो 60 वर्ष पूर्व घर से गुम है और उनका कोई पता नहीं है इस तरह से प्रतीत होता है कि श्री राम पाल अब इस द्निया में जीवित नहीं है तथा वह अब उनके भाई का विरास्त इन्तकाल करवाना चाहते है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से श्री राम पाल व सर्वसाधारण जनता उप महाल कामरु को सुचित किया जाता है कि अगर श्री राम पाल का विरास्त का इन्तकाल उनके जायज वारसान के नाम तस्दीक करने बारे स्वयं श्री राम पाल व किसी भी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज तिथि 5-12-2008 को अदालत में स्वयं या किसी भी प्राधिकृत एजेंट के द्वारा अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 4-11-2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सांगला,

तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

केस0 नं0 : त0 सां0 (रीडर) :---

तारीख फैसला :

श्री शिवानी कुमार पुत्र श्री जय लाल, गांव कामरु, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) . . प्राथी।

बनाम

आम जनता, उप–महाल कामरु, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

. . फरीकदोयम्।

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री शिवानी कुमार पुत्र श्री जय लाल, गांव कामरु, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उनका नाम श्री शिवानी कुमार से बदल कर शिवान नेगी रखना चाहते हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण जनता उप महाल कामरु को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त नाम समस्त अभिलेखों में शिवान नेगी दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज स्वयं या किसी प्राधिकृत एजेंट के द्वारा अपना एतराज अदालत में तिथि 5—12—2008 तक प्रस्तुत कर सकता है। अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उपरोक्त नाम समस्त अभिलेखों में शिवान नेगी दर्ज करने के आदेश पारित किये जायेंगे।

आज दिनांक 4-11-2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –

कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला,

तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

केस० नं0 : त० सां० (रीडर) :---

तारीख फैसला : 4-11-2008.

ईन्दर कुमारी पुत्री श्री जगत राम, गांव सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता, उप-महाल सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

. . फरीकदोयम।

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी ईन्दर कुमारी पुत्री श्री जगत राम, निवासी गांव सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र गुजारा है कि उनकी पुत्र श्री हेमन्त जिसकी जन्म तिथि 6—4—1998 है जोकि पंचायत रिकार्ड में 6—4—2000 गलत दर्ज हुई है जोकि अब ग्राम पंचायत सांगला में सही दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत सांगला में 6—4—1998 दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज स्वयं या किसी प्राधिकृत एजेंट के द्वारा अपना एतराज अदालत में तिथि 5—12—2008 तक प्रस्तुत कर सकता है। अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उपरोक्त जन्म तिथि सम्बन्धित ग्राम पंचायत में 6—4—1998 दर्ज करने के आदेश पारित किये जायेंगे।

आज दिनांक 4-11-2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —

कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला,

तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

केस० नं० : त० सां० (रीडर) :---

तारीख फैसला 4—11—2008.

श्रीमती ज्ञान भगती पत्नी श्री प्रेम राज, गांव सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता, उप–महाल सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

. . फरीकदोयम।

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्रीमती ज्ञान भगती पत्नी श्री प्रेम राज, निवासी गांव सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र गुजारा है कि उनका पुत्र वृजेश्वर सिंह जिसका जन्म दिनांक 5—8—1997 व पुत्री निधि जिसका जन्म दिनांक 4—1—1995 को हुई / हुआ है। उनकी जन्म तिथियां पंचायत पंजी में पंजीकृत नहीं हैं जोकि अब ग्राम पंचायत सांगला में पंजीकृत करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त नाम व जन्म तिथियां ग्राम पंचायत सांगला में पंजीकृत करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज स्वयं या किसी प्राधिकृत एजेंट के द्वारा अपना एतराज अदालत में तिथि 5–12–2008 तक प्रस्तुत कर सकता है। अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उपरोक्त नाम व जन्म तिथियां सम्बन्धित ग्राम पंचायत में पंजीकृत करने के आदेश पारित किये जायेंगे।

आज दिनांक 4-11-2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) केस० नं० त० सां० (रीडर) :— तारीख फैसला : 4—11—2008.

श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री वरुण कुमार, गांव सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता, उप–महाल सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

. . फरीकदोयम्।

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री वरुण कुमार, गांव सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र गुजारा है कि उनका पुत्र मोहित जिसका जन्म तिथि 7—4—1995 व पुत्री शिवानी जिसका जन्म तिथि 26—3—1996 है उनकी जन्म तिथियां पंचायत पंजी में पंजीकृत नहीं हैं जोकि अब ग्राम पंचायत सांगला में पंजीकृत करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त नाम व जन्म तिथियां ग्राम पंचायत सांगला में पंजीकृत करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज स्वयं या किसी प्राधिकृत एजेंट के द्वारा अपना एतराज अदालत में तिथि 5—12—2008 तक प्रस्तुत कर सकता है। अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उपरोक्त जन्म तिथियां सम्बन्धित ग्राम पंचायत में पंजीकृत करने के आदेश पारित किये जायेंगे।

आज दिनांक 4–11–2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री देवी सिंह नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) श्री जीत राम पुत्र श्री पौशु राम, निवासी पौण्डा, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा (13) 3 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री जीत राम पुत्र श्री पौशु राम, निवासी पौण्डा, तहसील निचार, जिला किन्नौर ने इस कार्यालय में एक शपथ–पत्र के साथ दरख्वास्त गुजारी है कि उसकी पुत्री शकीना जिसकी जन्म तिथि 25–4–2003 है। क्षेत्रीय पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है अब दर्ज करने बारा इस न्यायालय से अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त शकीना का नाम व जन्म तिथि पंचायत अभिलेख पौण्डा में दर्ज करने बारा किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 22—12—2008 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर होकर एतराज व उजर असालतन/वकालतन पेश कर सकता है।

अन्यथा अगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और उसके उपरान्त कोई उजर / एतराज समायत न होगा।

आज दिनांक 5–11–2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

देवी सिंह नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निचार स्थित भाबा नगर, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री देवी सिंह नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) श्री जय देविन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री प्रभू राम, निवासी पूनंग, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा (13) 3 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री जय देविन्द्र कुमार पुत्र स्व० श्री प्रभू राम, निवासी पूनंग, तहसील निचार, जिला किन्नौर ने इस कार्यालय में एक शपथ—पत्र के साथ दरख्वास्त गुजारी है कि उसकी पुत्री का सही नाम अवन्तीका है। लेकिन क्षेत्रीय पंचायत अभिलेख में सरिता दर्ज है जो गलत है। अब दरुस्त कर पुत्री का सही नाम अवन्तीका दर्ज करने बारा इस न्यायालय से अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सरिता के स्थान पर अवन्तीका पंचायत अभिलेख पूनंग में दर्ज करने बारा किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 22—12—2008 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर होकर एतराज व उजर असालतन/वकालतन पेश कर सकता है।

अन्यथा अगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और उसके उपरान्त कोई उजर/एतराज समायत न होगा।

आज दिनांक 5-11-2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

देवी सिंह नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निचार स्थित भाबा नगर, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री देवी सिंह नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) श्री जीत राम पुत्र श्री पौशु राम, निवासी पौण्डा, तहसील निचार, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा (13) 3 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969. प्रार्थी श्री जीत राम पुत्र श्री पौशु राम, निवासी पौण्डा, तहसील निचार, जिला किन्नौर ने इस कार्यालय में एक शपथ—पत्र के साथ दरख्वास्त गुजारी है कि उसकी पुत्री काजल कुमारी जिसकी जन्म तिथि 18—7—2004 है। क्षेत्रीय पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है अब दर्ज करने बारा न्यायालय से अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त काजल कुमारी का नाम व जन्म तिथि पंचायत अभिलेख पौण्डा में दर्ज करने बारा किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 22–12–2008 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हाजिर होकर एतराज व उजर असालतन / वकालतन पेश कर सकता है।

अन्यथा अगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और उसके उपरान्त कोई उजर/एतराज समायत न होगा।

आज दिनांक 5–11–2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

देवी सिंह नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निचार स्थित भाबा नगर, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)। ब अदालत श्री N. D. Bhatia, नायब तहसीलदार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि० प्र०)

श्री हेम राज s/o श्री रतन दास, निवासी शाडला, डाकघर कटीन्डी, तहसील सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री हेम राज s/o श्री रतन दास, निवासी शाडला, डाकघर कटीन्डी, तहसील सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय शपथ पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उनकी माता चगारी देवी की मुत्य दिनांक 15—12—1989 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उसकी मृत्यु तिथि एम0 सी0 कटीन्डी के रिकार्ड में दर्ज नही करा सका।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 10–12–2008 को असालतन या वकालतन प्रातः 10.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपित्त प्राप्त न होने पर प्रार्थना–पत्र श्री हेम राज पुत्र श्री रतन दास पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 1-10-2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

N. D. BHATIA, नायब तहसीलदार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री N. D. Bhatia, नायब तहसीलदार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री सुरजीत सिंह s/o श्री सरदार सिंह, निवासी H. No. 357/12 राम नगर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सुरजीत सिंह s/o श्री सरदार सिंह, निवासी H. No. 357/12 राम नगर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय शपथ पत्र सिंहत मुकद्दमा दायर किया है कि उनके पुत्र मनदीप सिंह का जन्म दिनांक 19—8—1970 व पुत्री बेला का जन्म तिथि 30—5—1972 को हुई है परन्तु अज्ञानतावश उनकी जन्म तिथियां एम0 सी0 मण्डी के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 25—11—2008 को असालतन या वकालतन प्रातः 10.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर प्रार्थना—पत्र श्री सुरजीत सिंह पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। आज दिनांक 5-10-2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

N. D. BHATIA, नायब तहसीलदार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत उप-पंजीकाध्यक्ष सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मुकद्दमा शीर्षक :

श्री व्यास देव, श्री भागमल, श्री तेज सिंह पुत्र व सितु देवी पुत्री श्री वेली राम, निवासी मन्योह लाम्बरी, ईलाका अन्तपुर, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

इश्तहार राजपत्र

उपरोक्त

उपरोक्त मुकद्दमा में प्रार्थीगण ने इस अदालत में एक प्रार्थना—पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया कि श्रीमती मालती देवी विधवा श्री वेली राम, निवासी मन्योह लाम्बरी, डाकघर टिहरा, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने दिनांक 22—8—2008 को एक वसीयतनामा वहक प्रार्थीगण के नाम करवाया है जो विला पंजीकृत है। वसीयतकर्त्ता दिनांक 24—8—2008 को फौत हो चुका है।

अतः आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वसीयत को पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 8—12—2008 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी कर सकते हैं। गैर हाजिरी की सूरत में कार्यवाही एक पक्षीय अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 25-10-2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / – उप–पंजीकाध्यक्ष सरकाघाट जिला मण्डी (हि० प्र०)।

ब न्यायालय श्री राकेश ठाकुर, सहायक समाहर्ता एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

मुकद्दमा शीर्षक :

श्री सुख राम पुत्र श्री सन्तू राम, निवासी नागण, डाकघर पिंगला, ईलाका भदरोता, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी।

विषय.--नाम दरुस्ती :

प्रार्थी उपरोक्त ने प्रार्थना—पत्र इस आशय से इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का सही नाम सुख राम है। परन्तु पंचायत रिकार्ड नागण में गलती से साधु दर्ज है। प्रार्थी इसे दरुस्त करवाना चाहता है।

अतः आम जनता को बजिरया इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्त करने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन हाजिर न्यायालय आकर मिति 4–12–2008 को पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। गैर हाजिर की सूरत में कार्यवाही एक पक्षीय अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 30-10-2008 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

राकेश ठाकुर, सहायक समाहर्ता एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री एम0 डी0 राकेश, कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री बुधि सिंह s/o श्री नन्दा राम Nanda Ram, निवासी जरल कलौनी, डाकघर पन्डोह, तहसील सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री बुधि सिंह s/o श्री नन्दा राम Nanda Ram, निवासी जरल कलौनी, डाकघर पन्डोह, तहसील सदर मण्डी, जिला मण्डी ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय शपथ पत्र सिंहत मुकद्दमा दायर किया है कि उनका स्वयं का बुधि सिंह पुत्र श्री नन्दा राम का जन्म दिनांक 17—12—1980 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत सियोग के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 10–12–2008 को असालतन या वकालतन प्रातः 10.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर प्रार्थना–पत्र श्री बुधि सिंह पुत्र श्री नन्दा राम पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 24-9-2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

एम० डी० राकेश, कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि० प्र०)। ब अदालत श्री एम0 डी0 राकेश, कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

श्री बली केसर s/o श्री कहनू राम, निवासी बिजनी, डाकघर बिजनी, तहसील सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यू पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री बली केसर s/o श्री कहनू राम, निवासी बिजनी, डाकघर बिजनी, तहसील सदर मण्डी, जिला मण्डी ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय शपथ पत्र सिहत मुकद्दमा दायर किया है कि उनके पौत्र पुष्प राज पुत्र श्री तिलक राज का जन्म दिनांक 27—9—2003 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत बिजनी के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 10–12–2008 को असालतन या वकालतन प्रातः 10.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई आपित्त प्राप्त न होने पर प्रार्थना–पत्र श्री बली केसर पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 24-9-2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

एम0 डी0 राकेश, कार्यकारी दण्डाधिकारी, सदर मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री बी० सी० मिश्रा, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप—तहसील कोटली, जिला मण्डी (हि० प्र०)

श्री नेक राम पुत्र श्री शान्धी राम, निवासी गांव सुखसाल, डाकघर समराहन, ईलाका तुगंल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र मय शपथ पत्र इस आशय से गुजारा है कि मेरा वास्तविक नाम नेक राम है जोकि स्कूल प्रमाण—पत्र में दर्ज है। परन्तु राजस्व व ग्राम पंचायत में मेरा नाम रेव सिंह दर्ज है। जिस में नाम दरुस्ती के आदेश दिये जावे।

अतः सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि उक्त प्रार्थी के नाम दरुस्ती बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16–12–2008 या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न होने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेगे।

आज दिनांक 31-10-2008 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

बी० सी० मिश्रा, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप—तहसील कोटली, जिला मण्डी (हि० प्र०)।